खोदा पहाड़, निकली चुहिया है 100 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा: शेखावत

प्रधानमंत्रीजी की सभा की सफलता को देखकर आंखें चौंधिया गईं, इसीलिए आनन-फानन में घोषणा की

- केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री ने पूछा, फरवरी में बजट में यह घोषणा की थी, अब तक लागू नहीं की।
- गजेन्द्र सिंह ने यह भी कहा, कांग्रेस के गारंटी कार्ड पहले ही फेल हुए, फेल गारंटी कार्ड दोबारा नहीं चला सकते।

जयपुर/नई दिल्ली, 1 जून (का.सं.)। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, 100 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा को "खोदा पहाड़, निकली चुहिया" बताया। उन्होंने कहा कि, यह घोषणा तो वह बजट भाषण में भी कर चुके थे। फरवरी से लेकर अब तक उसको लागू नहीं किया था। शेखावत ने कहा कि, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में विजय होना उतना ही सुनिश्चित है, जितना यह कि, कल का सूर्योदय पूर्व दिशा से होगा।

गुरुवार को एक चैनल से बातचीत में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि, प्रधानमंत्रीजी की सभा की सफलता को देखकर मुख्यमंत्रीजी की आंखें चौंधिया गई थीं, इसलिए आनन-फानन में उन्होंने बयान दिया कि, एक घोषणा करूँगा। राजस्थान के लोग सोच रहे थे कि, पता नहीं क्या करने वाले हैं? फिर रात को खोदा पहाड़, निकली चुहिया। सौ यूनिट बिजली फ्री देंगे, यह घोषणा तो वह पहले बजट भाषण में भी कर चुके थे। फरवरी से लेकर अब तक उसको लागू नहीं किया। उल्टा लोगों पर फ्यूल सरचार्ज बोझ लाद दिया, फिक्स चार्जेज़ का बोझ बढ़ा दिया गया। अब एकाएक राहत शिविरों में जाकर उनको एहसास हुआ और फीडबैक मिला।

शेखावत ने कहा, मुझे लगता है कि, बिना अध्ययन के घोषणा कर देने का, बिना हकीकत को जाने उनको लागू कर देने का और उसके कारण होने वाली विफलता का यह नायाब उदाहरण है।

केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि, राजस्थान के डिस्कॉम्स पर 1.20 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। जब 2014 में नरेंद्र मोदीजी प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने सभी प्रदेशों के डिस्कॉम के लिए एक योजना बनाकर कर्ज को लॉन्ग टर्म लोन में चेंज किया था। आज वापस हम 1.20 लाख करोड़ के कर्जे पर आकर खड़े हुए हैं। राजस्थान सरकार को, अभी तक के फ्यूल सरचार्ज को, जो उन्होंने सब्सिडाइज़ किया है, उसके पेटे में भी 15,180 करोड़ रुपए डिस्कॉम्स को चुकाना बाकी हैं, पहले उनको चुकाएं। उनको नहीं चुकाने के कारण उनके वित्तीय हालात खराब हुए हैं। फायनैंशियल संस्थाएं लोन नहीं दे रही हैं, उसके कारण कोयले का पेमैंट नहीं हो रहा है, उसके कारण राजस्थान में बिजली कटौती चल रही है। एकतरफ आप कटौती कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह की घोषणा कर रहे हैं।

शेखावत ने कहा, "जहां तक घोषणाओं का प्रश्न है, मैं कहना चाहता हूं कि, राजस्थान की जनता के साथ, वर्ष 2018 में गहलोत साहब और उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने एक से दस तक गिनती गिनकर घोषणाएं की थीं। वो घोषणाएं जिस तरह से राजस्थान के किसानों, महिलाओं, युवाओं, बेरोजगारों के लिए एक मजाक बनीं, उन्होंने महसूस किया कि उनके साथ धोखा हुआ है। मुझे लगता है कि छोटी-छोटी रेवड़ियां बांटने का अब कोई प्रभाव नहीं होगा।"

कांग्रेस पार्टी के गारंटी कार्ड पर शेखावत ने कहा कि, राजस्थान में गारंटी पहले ही फेल हुई है, जो फेल गारंटी कार्ड है, वह गारंटी कार्ड दोबारा चला नहीं करते। उन्होंने कहा कि, हिंदी की कहावत है, दूध का जला छाछ को भी फूंक कर पीता है। राजस्थान के किसान, युवा, बेरोजगार, महिलाएं पिछली बार धोखा खा चुके हैं, एक धोखा और नहीं खा सकते हैं।

प्रसूता की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जांच करवाने के निर्देश जिला कलेक्टर करौली को दिए थे। जिला कलेक्टर करौली द्वारा गठित टीम ने मामले की जांच एक दिन में पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुति की।

जांच रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया चिकित्साधिकारी डॉ. राधेश्याम बैरवा, नर्सिंग अधिकारी नाथू मीणा एवं ए.एन.एम. मनीषा मीणा को ड्यूटी में लापरवाही का दोषी पाये जाने पर उन्हें ए.पी.ओ. कर दिया गया है।

मई में जी.एस.टी संग्रह 1.57 लाख करोड़ के पार पहुँचा

नयी दिल्ली 1 जून (वार्ता)। गुड्स एण्ड सर्विसेज़ टैक्स (जी.एस.टी.) राजस्व संग्रह इस वर्ष मई में 1.57 लाख करोड़ रुपये रहा जो मई 2022 में संग्रहित 140885 करोड़ रुपये की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक है। मई 2023 में संग्रहित राजस्व जी.एस.टी.के लागू होने के बाद पांचवी बार कलैक्शन 1.5 लाख करोड़ रुपये के पार रहा है।

इस वर्ष अप्रैल में रिकार्ड 1.87 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी राजस्व संग्रहित हुआ था जो अब तक का सर्वाधिक राजस्व था। इससे पहले पिछले वर्ष अप्रैल में यह राशि

- मई 2022 के मुकाबले इस चालू वित्त वर्ष में जी.एस.टी कलैक्शन में 12 प्रतिशत की तेजी आई है, मई 2022 में करीब 1.40 लाख करोड़ रु. का जी.एस.टी. कलैक्शन हुआ था।

167540 करोड़ रुपये रहा था। पिछले 14 महीने से जीएसटी राजस्व संग्रह 1.40 लाख करोड़ रुपये से अधिक बना हुआ है। मार्च 2023 में यह 160122 करोड़ रुपये रहा था।

वित्त मंत्रालय ने आज यहां जीएसटी राजस्व संग्रह का आंकड़ा जारी किया जिसमें मई 2023 में संग्रहित राजस्व 157090 करोड़ रुपये रहा है। इस वर्ष अप्रैल में संग्रहित राजस्व में सी.जी.एस.टी. 28411 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 35828 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 81363 करोड़ रुपये रहा जिसमें आयात पर संग्रहित कर 41772 करोड़ रुपये शामिल है।

एन.सी.ई.आर.टी....

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लगाया था कि, एन.सी.ई.आर.टी. ने अपनी बारहवीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में सिखों के बारे में ऐतिहासिक जानकारी गलत तरह से प्रस्तुत की है। एस.जी.पी.सी. की आपत्ति पुस्तक "स्वतंत्रता तक भारत में राजनीति" में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के उल्लेख से संबंधित है।

पहलवानों के मुद्दे पर किसान संगठन आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे

भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख राकेश टिकैत ने कहा कि, जरूरत पड़ी तो हम राष्ट्रपति से मिलकर सरकार के रवैये की शिकायत करेंगे

- किसान नेता राकेश टिकैत ने गुरुवार को कहा कि, हरियाणा के किसान और खाप पंचायतें पहलवानों को खुला समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने पहलवानों के विरोध के मुद्दे पर अंतिम फैसला कल शुक्रवार को हरियाणा में होने वाली बैठक में लिया जाएगा।
- राकेश टिकैत ने स्पष्ट कर दिया कि, वे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और पहलवानों को न्याय दिलाने तक किसानों का यह प्रदर्शन जारी रहेगा।

नई दिल्ली, 1 जून। रैसलिंग फैडरेशन ऑफ इंडिया (डब्ल्यु. एफ.आई.) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तार की मांग कर रहे पहलवानों को किसानों और खाप का समर्थन मिला है। किसान नेता राकेश टिकैत ने गुरुवार को कहा कि पहलवानों के विरोध के मुद्दे पर अंतिम फैसला कल शुक्रवार को हरियाणा में होने वाली बैठक में लिया जाएगा। हरियाणा के किसान और खाप पहलवानों को खुला समर्थन दे रहे हैं। पहलवानों और बृजभूषण शरण सिंह के बीच चल रहे टकराव के बीच बृहस्पतिवार को शोरम गांव में खाप महापंचायत शुरू हुई है।

भारतीय किसान यूनियन (बी.के.यू.) के नेता राकेश टिकैत ने गुरुवार को कहा कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ शीर्ष पहलवानों के चल रहे विरोध को लेकर एक समिति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगी। पत्रकारों से बात करते हुए राकेश टिकैत ने पूछा कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ दर्ज पॉक्सो मामले में अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई।

राकेश टिकैत ने स्पष्ट कर दिया कि, वे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और पहलवानों को न्याय दिलाने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने आज मुजफ्फरनगर में एक विशाल बैठक में पहलवानों से कहा, "अगर जरूरत पड़ी तो हम भारत के राष्ट्रपति के पास जाएंगे... हम आपके साथ हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।" भारतीय किसान यूनियन के एक नेता ने कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर चल रहे पहलवानों के विरोध पर चर्चा के बाद खाप अपना प्रस्ताव पारित करेगी।

दिल्ली पुलिस ने डब्ल्यूएफआई प्रमुख के खिलाफ दो एफ आई आर दर्ज की हैं। जहां पहली एफ.आई.आर एक नाबालिग पहलवान के आरोपों से संबंधित है और पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज की गई है, वहीं दूसरी अपमानजनक शील से संबंधित है। राकेश टिकैत ने जोर देकर कहा, "बृज भूषण सिंह के खिलाफ दर्ज पॉक्सो मामले में कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्या कानून में संशोधन होगा कि पॉक्सो अधिनियम के तहत किसी को गिरफ्तार करने से पहले एक जांच होगी?"

प्रदर्शनकारी पहलवानों के समर्थन में उतरे किसान नेता ने भारतीय जनता पार्टी पर अपने ही आदमियों का विरोध करने का भी आरोप लगाया। बता दें बृजभूषण सिंह उत्तर प्रदेश से बीजेपी सांसद हैं।

262 लाख टन गेहूं की खरीद

नयी दिल्ली, 1 जून (वार्ता)। रबी के मौसम में 2023-24 के दौरान गेहूं की खरीद 262 लाख टन तक पहुंच गयी है जो पिछले साल हुई 188 लाख टन खरीद की तुलना में 74 लाख टन अधिक है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की गुरुवार को जारी एक विज्ञप्ति में 30 मई तक के आंकड़ों के आधार पर यह जानकारी दी गयी।

मानसून सत्र में अडानी मामले में जे.पी.सी. जांच की पुरजोर मांग उठायेगी कांग्रेस

कांग्रेस ने इस मामले में सरकार को घेरने के लिए "हम अडानी के कौन हैं?" शीर्षक से 100 सवालों की पुस्तिका जारी की

नयी दिल्ली 1 जून (वार्ता)। अडानी मामले की संयुक्त संसदीय समिति (जे.पी.सी.) से जांच कराने की विपक्ष की मांग का नेतृत्व कर रही कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि वह संसद के आगामी मानसून सत्र में जे.पी.सी. की अपनी मांग पर जोर देगी।

कांग्रेस के प्रभारी महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने अदानी मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पार्टी की ओर से पूछे गये 100 सवालों को लेकर हम अडानी के हैं कौन शीर्षक से पुस्तिका जारी करने के बाद संवाददाताओं से कहा, संसद के आगामी मानसून सत्र में जब हम नये संसद भवन में बैठेंगे, तो हमारी पहली मांग मोदानी घोटाले की जे.पी.सी. जांच होगी।

कांग्रेस सांसद ने कहा, सभी विपक्षी दल एकजुट हैं। हम जेपीसी जांच की मांग करेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। जे.पी.सी. जांच से ही मोदनी घोटाले का पर्दाफाश हो सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की ओर से मोदानी घोटाले पर पूछे गए 100 सवालों पर उन्हें (मोदी) अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए।

गौरतलब है कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि अडानी समूह दशकों से स्टॉक हेरफेर और अकाउंटिंग धोखाधड़ी योजनाओं में लिप्त रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर अरबपति व्यावसायी गौतम अडानी समेत कुछ उद्योगपतियों का पक्ष लेने का आरोप लगाते रहे हैं। उन्होंने मोदी से अडानी के साथ अपने संबंधों का खुलासा करने के लिए कहा था।

मुण्डे बहनों का...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रीतम को भी ऐसे संकेत दिए गए है कि उन्हे 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा। दोनों बहनें इसलिए भी गुस्सा है कि अप्रैल में जी.एस.टी. अधिकारियों ने पंकजा की एक शुगर मिल पर रेड की थी। पंकजा ने तब भी अपनी नाराज़गी जता दी थी और कहा था कि जी.एस.टी. के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि रेड के आदेश ऊपर से आए हैं। तब शिव सेना के उद्धव ठाकरे गुट उनके समर्थन में आगे आया था। पूर्व में भी पंकजा ने कई बार भाजपा के राज्य नेताओं की आलोचना की थी और वे अक्सर ऐसे संकेत देती रहती है कि वर्तमान उप मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनवीस उन्हें दरकिनार करने का प्रयास कर रहे हैं। मुंडे बहिनों को अपने पिता गोपीनाथ मुंडे की विरासत का समर्थन प्राप्त है जो कि महाराष्ट्र में भाजपा के प्रमुख ओ.बी.सी. नेता थे। मुंडे ने ही महाराष्ट्र में भाजपा का शिव सेना व तीन अन्य छोटे दलों के साथ गठबंधन बनवाया था। मुंडे और उनके साले प्रमोद महाजन को महाराष्ट्र में भाजपा को खड़ा करने का श्रेय दिया जाता है। उन्हीं की मेहनत थी कि 1995 में भाजपा सत्ता के करीब पहुंची थी। आगामी लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों से पहले मुंडे बहिनों का विद्रोह भाजपा के लिए परेशानियां पैदा कर सकता है।

वॉट्सऐप ने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक है और भारत में इसके लगभग 50 करोड़ यूज़र्स हैं। वॉट्सऐप ने कहा, "इन्फॉर्मेशन टैक्नॉलजी नियम 2021 के अनुसार, हमने अप्रैल 2023 के महीने के लिए अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस यूज़र-सैफ्टी रिपोर्ट में कंपनी को यूज़र्स से मिली शिकायतों की डिटेल और वॉट्सऐप द्वारा की गई कार्रवाई के साथ-साथ वॉट्सऐप की अपनी प्रिवेंटिव कार्रवाइयां की डिटेल शामिल हैं। जैसा कि, नई मंथली रिपोर्ट में दिखाया गया है, वॉट्सऐप ने अप्रैल के महीने में 7.4 मिलियन (74 लाख) से अधिक अकाउंट्स पर बैन लगा दिया।

भारत नेपाल रिश्तों को सुपरहिट बनाएंगे मोदी-प्रचंड

नयी दिल्ली, 1 जून (वार्ता) भारत एवं नेपाल ने अपने सदियों से चले आ रहे घनिष्ठ संबंधों में 'विकास साझीदारी' को 'सुपरहिट' बनाने का संकल्प लिया और रेल, हवाई, जलीय कनेक्टिविटी तथा पेट्रोलियम पाइपलाइन, विद्युत पारगमन लाइनों को विस्तार देने की छह परियोजनाओं को आज क्रियान्वित किया और पारगमन संधि सहित सात समझौतों पर हस्ताक्षर किये।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड के बीच आज यहां हैदराबाद हाउस में हुई द्विपक्षीय बैठक में ये निर्णय लिये गये। बैठक में रक्सौल से काठमांडू तक रेलवे लाइन बिछाने की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट नेपाली पक्ष को सौंपी गयी। इसके अलावा भारत ने नेपाल से दस साल तक दस हजार मेगावाट जलविद्युत खरीदने का भी समझौता किया। नेपाल के प्रधानमंत्री दहल ने प्रधानमंत्री मोदी को नेपाल यात्रा पर आने के लिए निमंत्रित भी किया।

बैठक के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से रिमोट कंट्रोल के माध्यम से जयनगर-कुर्था रेलवे लाइन के बिजलपुरा तक विस्तार का लोकार्पण किया। भारतीय अनुदान के तहत नवनिर्मित रेल लिंक बथनाहा (भारत) से नेपाल सीमा शुल्क यार्ड तक एक भारतीय रेलवे कार्गो ट्रेन का हरी झंडी दिखा कर शुभारंभ किया। इसके अलावा नेपालगंज (नेपाल) और रुपईडीहा (भारत) में एकीकृत चेकपोस्ट (आईसीपी) का उद्घाटन किया तथा भैरहवा (नेपाल) और सोनौली (भारत) में आईसीपी, मोतिहारी-अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन के तहत दूसरे चरण की सुविधा और दोनों देशों के उपक्रमों पीजीसीआईएल और एनईए के संयुक्त रूप से बनाई जा रही गोरखपुर-बुटवल विद्युत पारेषण लाइन के भारतीय हिस्से का शिलान्यास किया।

इसके बाद दोनों देशों के बीच पारगमन संधि के हस्ताक्षिरत दस्तावेज के आदान प्रदान के अलावा मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन के चितवन तक विस्तार, सिलीगुड़ी से पूर्वी नेपाल के झापा तक एक अन्य पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछाने एवं चितवन और झापा में नए पेट्रोलियम भंडार स्थापित करने के समझौते, भारत-नेपाल सीमा पर दोधरा चांदनी चेक पोस्ट के बुनियादी ढांचे के निर्माण, सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस (एसएसआईएफएस) और इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन अफेयर्स, नेपाल के बीच सहयोग के करार, सीमा पार भुगतान के लिए एनपीसीआईएल और एनसीएचएल, नेपाल के बीच सहयोग के समझौते, सतलुज जलविद्युत निगम और नेपाल निवेश बोर्ड के बीच लोअर अरुण जलविद्युत परियोजना के विकास के समझौते तथा फुकोट-करनाली जलविद्युत परियोजना के विकास के लिए एनएचपीसी और वीयूसीएल, नेपाल के बीच करार के दस्तावेजों का भी आदान प्रदान किया गया।

मोदी ने अपने प्रेस वक्तव्य में कहा, मुझे याद है, 9 साल पहले 2014 में कार्यभार संभालने के 3 महीने के भीतर, मैंने नेपाल की अपनी पहली यात्रा की थी। उस समय मैंने भारत-नेपाल संबंधों के लिए 'हिट' यानी (हाईवेज़, आईवेज़ एवं ट्रांसवेज़) फार्मूला दिया था। मैंने कहा था कि भारत-नेपाल के बीच ऐसे संबंध स्थापित करेंगे कि हमारी सीमाएं बाधा न बनें। ट्रकों की जगह पाइपलाइन से तेल का निर्यात होना चाहिए। साझा नदियों के ऊपर सेतु बनाने चाहिए। नेपाल से भारत को बिजली निर्यात करने के लिए सुविधाएं बनाई जानी चाहिए। आज, 9 साल बाद, मुझे कहते हुए ख़ुशी है कि हमारी साझीदारी वाकई में 'हिट' है।

उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में हमने अनेक क्षेत्रों में कई उपलब्धियाँ हासिल की हैं। बीरगंज में नेपाल की पहली एकीकृत जांच चौकी बनाई गयी। भारत-नेपाल के बीच हमारे क्षेत्र की पहली सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाई गयी। हमारे बीच पहली ब्रॉड-गेज रेल लाइन स्थपित की गयी है। सीमा पार नई पारेषण लाइनों का निर्माण किया गया है।

टाटा कंसल्टैंसी सर्विसेज देश का सबसे टॉप ब्रैंड घोषित हुआ

- ब्रैंड वैल्यू के मामले में रिलायंस दूसरे और इन्फोसिस तीसरे स्थान पर है।

नई दिल्ली 1 जून (वार्ता)। भारत के शीर्ष 50 सबसे मूल्यवान ब्रांडों की सूची में 1,09,576 करोड़ रुपये के ब्रैंड मूल्यांकन के साथ टाटा समूह की सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी टाटा कंसलटेंसी सर्विसेस (टी.सी.एस.) शीर्ष स्थान पर है।

इस सूची में शामिल पांच प्रमुख ब्रैंड्स का मूल्यांकन 100 अरब डॉलर से अधिक है और इसमें अरबपति मुकेश अंबानी के दो ब्रैंड रिलायंस और जियो भी शामिल है।

दुनिया की प्रमुख ब्रैंड कंसल्टेंसी कंपनी इंटरब्रांड द्वारा जारी इस सूची में टीसीएस के बाद रिलायंस दूसरे पायदान पर तो जियो को पांचवा स्थान मिला है। रिलायंस का ब्रांड मूल्य 65,320 करोड़ रुपये आंका गया है। जबकि 49,027 करोड़ के ब्रांड मूल्यांकन के साथ जियो पांचवे स्थान पर बनी हुई है। दिलचस्प है कि जियो ने पहली बार इस लिस्ट में जगह बनाई है, वहीं दिग्गज दूरसंचार कंपनी एयरटेल छठे नंबर पर है। आईटी कंपनी इंफोसिस 53,323 करोड़ के ब्रांड वैल्यू के साथ तीसरे तथा देश का शीर्ष प्राइवेट बैंक एचडीएफसी 50,291 करोड़ रुपये के ब्रांड वैल्यू के साथ चौथे स्थान पर है।

इंटरब्रांड के आंकड़ों से खुलासा हुआ है कि लिस्ट में शामिल 50 कंपनियों का कुल ब्रांड मूल्यांकन पहली बार 100 अरब डॉलर को पार कर गया है। शीर्ष तीन ब्रांड टीसीएस, रिलायंस और इंफोसिस का ब्रांड मूल्य, सूची में शामिल पहली 10 कंपनियों के कुल ब्रांड मूल्य का 46 फीसदी आंका गया है। वहीं शीर्ष दस कंपनियों के ब्रांड का कुल ब्रांड मूल्य, सूची में शामिल शेष 40 ब्रांडों के संयुक्त मूल्य से भी अधिक है।

एलआईसी, महिंद्रा, एसबीआई और आईसीआईसीआई भी पहले 10 मूल्यवान भारतीय ब्रांड में शामिल हैं। इनके अलावा टाटा, अदाणी, मारूति सुजुकी, आईटीसी, बजाज ऑटो, अमूल, डाबर, पतंजलि और ब्रिटेनिया जैसे ब्रांड भी पहले 50 की लिस्ट में शामिल हैं।

शरद पवार...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दोनों नेताओं के बीच यह पहली बैठक है और इसे राज्य की राजनीति में सबसे बड़े घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। यह मीटिंग इस लिहाज से भी खास है क्योंकि शिवसेना के दूसरे धड़े के नेता उद्धव ठाकरे छुट्टियां मनाने के लिए विदेश में हैं। दोनों के बीच आधे घंटे से अधिक समय तक बंद कमरे में बातचीत हुई। हालांकि इस बैठक में हुई चर्चा का ब्योरा सामने नहीं आया, लेकिन कहा गया कि पवार उन्हें मराठा मंदिर संस्था के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए वर्षा बंगले गए थे। ऐसा कहा जाता है कि शरद पवार जब भी राज्य के मुखिया के सामने महत्वपूर्ण मुद्दे रखना चाहते हैं, तो वे खुद मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर जाते हैं। यह भी संभावना जताई जा रही है कि शरद पवार चीनी मिल के सिलसिले में मुख्यमंत्री से चर्चा करने गए थे। हालांकि राजनीतिक हलकों की निगाहें इस मुलाकात पर टिकी हैं।

'चीन के पत्रकारों को भारत स्वतंत्र...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भारत पर "जैसे को तैसा" वीज़ा-विवाद का दोषारोपण किया था, जिसके अन्तर्गत उन्होंने तत्काल प्रभाव से एक-दूसरे के पत्रकारों को निष्कासित कर दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार पर मनमाने तरीके से चीनी पत्रकारों के वीज़ा की अवधि कम कर देने तथा 2020 के बाद वीज़ा नवीनीकरण न करने का आरोप लगाया था। विदेश मंत्रालय ने कहा था, "भारत में बचे अंतिम चीनी पत्रकार का वीज़ा भी समाप्त हो गया है।"

"ग्लोबल टाइम्स" ने "भारत द्वारा पत्रकारों का निष्कासन एक तुच्छ कार्यवाही है" शीर्षक से प्रकाशित सम्पादकीय में कहा है," इस कार्यवाही से नकारात्मक संदेश गया है तथा इसका चीन और भारत के बीच के मीडिया कम्यूनिकेशन पर निश्चित रूप से नकारात्मक असर पड़ेगा।" सम्पादकीय में इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत की एन.एस.जी. की सदस्यता का विरोध करके चीन किसी असम्मानजनक रूप में नहीं आ रहा था, क्योंकि वह इस नियम का पालन कर रहा था कि सभी एन.एस.जी. सदस्यों के लिये "नॉन-प्रॉलिफरेशन ट्रीटी (एन.पी.टी.) का हस्ताक्षरकर्ता (सिग्नेटरी) होना जरूरी है।

इन रिपोर्टों, कि चीन बदले की कार्यवाही करते हुये भारतीय पत्रकारों की वीज़ा-नवीनीकरण अर्जियों को रोक रहा है, की प्रतिक्रिया में, माओ ने इस प्रकार के कदम का उल्लेख किये बिना कहा कि बीजिंग के पास "समुचित जवाबी कदम उठाने के अलावा, और कोई विकल्प है ही नहीं।" भारत के "द हिन्दू" अखबार के संवाददाता अनन्त कृष्णन ने ट्विटर पर लिखा कि इस समय "बीजिंग में भारत का केवल एक ही प्राधिकृत पत्रकार बचा है।"

डब्ल्यू.एस.जे. रिपोर्ट में एक चीनी अधिकारी का हवाला देते हुये कहा है कि इस साल के शुरु में चीन में चार भारतीय पत्रकार थे, जिनमें से दो लोगों को चीन वापस जाने का वीज़ा नहीं दिया गया है। तीसरे पत्रकार से इस महीने कह दिया गया था कि इसकी मान्यता रद्द कर दी गई है लेकिन वह देश में ही रहेगा।

इस प्रकार के भेदभाव का जवाब देते हुये, प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, "चीनी पत्रकारों के साथ लम्बे समय से अनुचित एवं भेदभावपूर्ण व्यवहार हो रहा है। 2019 में अनुचित एवं भेदभावपूर्ण व्यवहार हो रहा है। 2017 में भारत ने भारत में काम कर रहे चीनी पत्रकारों के वीज़ा की वैधता बिना किसी वैध कारण के, कम करके तीन माह, बल्कि एक माह भी कर दी थी। 2020 के बाद, चीनी पत्रकारों की भारत में ठहरने की अर्जियों पर न पुनर्विचार किया और न मंजूरी ही दी। इसके परिणामस्वरूप, भारत में काम करने वाले चीनी पत्रकारों की संख्या, जो सामान्यत: 14 होनी थी एक एक रह गई।"

अखबार का दावा है कि चीन के प्रति भारत की नीति सख्त होती जा रही है तथ विशेषज्ञों को चेतावनी दी है कि चीन-भारत के रिश्तों की बेहतरी में विघ्न डालने के लिये जानबूझकर प्रतिकूल एवं शत्रुतापूर्ण माहौल पैदा किया जा रहा है। अखबार का कहना है कि इस मुद्दे का सार यह है कि भारत ने शीत युद्ध की मानसिकता बना ली है तथा वह चीन को अपने लिये "सबसे बड़ा संकट" मानता है।

ग्लोबल टाइम्स ने यह भी कहा है कि चीन और भारत के बीच के रिश्ते इन दिनों बिगड़ते जा रहे हैं, जबकि चीन इन्हें सुधारने के प्रयास कर रहा है। विशेषज्ञ चेतावनी देते हुये कह रहे हैं कि यह एक खतरनाक स्थिति है, क्योंकि भारत-चीन से टकराने तथा अमेरिका के साथ जुड़ने के लिये कटिबद्ध प्रतीत हो रहा है।

'हैलो...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे भारतीय मूल के शिक्षाविदों से चल रहे संवाद के बीच उन्होंने कहा, "यहां भारत से आये युवा विद्यार्थियों का एक ग्रुप है। मैं उनसे जुड़ना तथा उनसे बात करना चाहता हूँ। ऐसा करना मेरा अधिकार है। उन्होंने जोर देते हुए यह भी कहा कि इस यात्रा की तरह, उनकी प्राय: होने वाली विदेश यात्राओं में, वे किसी से कोई समर्थन/सहयोग की इच्छा नहीं कर रहे हैं।स्टैनफर्ड के पूरी तरह खचाखच भरे ऑडिटोरियम में उपस्थित श्रोताओं की करतल ध्वनि के बीच उन्होंने कहा, "मैं नहीं समझ पा रहा कि प्रधानमंत्री यहां आकर यह सब क्यों नहीं करते।" कार्यक्रम के संचालक/नियामक ने कहा कि स्टैनफर्ड में प्रधानमंत्री के आने का तथा विद्यार्थियों एवं शिक्षाविदों के साथ संवाद करने का हर समय स्वागत है।

अजीत डोभाल ने दहल से मुलाकात की

नयी दिल्ली, 1 जून। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने बुधवार शाम यहां नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' से शिष्टाचार मुलाकात की।

नेपाली दैनिक समाचार पत्रों ने बताया कि दहल और एनएसए श्री डोभाल के साथ विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा भी थे। दहल भारत की चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं।

इससे पहले दहल बुधवार दोपहर नयी दिल्ली पहुंचे। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद दहल प्रचंड मौर्या होटल गए, जहां उन्होंने भारतीय राजनयिकों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। नेपाल के प्रधानमंत्री गुरुवार को राजघाट पर पुष्पांजलि अर्पित कर नयी दिल्ली में अपनी कूटनीतिक व्यस्तताओं की शुरुआत करेंगे। बाद में वह हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों पक्षों की ओर से समझौतों का आदान-प्रदान और प्रेस वक्तव्य होंगे।

अमित शाह ने मणिपुर में हिंसा प्रभावितों के लिए राहत पैकेज का एलान किया

- गृहमंत्री ने अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ अभियान चलाने की भी घोषणा की और अवैध हथियार रखने वालों को पुलिस के सामने हथियार डालने को कहा।

इंफाल, 1 जून (वार्ता) मणिपुर के दौरे पर आए केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए गुरुवार को राहत पैकेज की घोषणा करते हुए राज्य में जनजातीय समुदायों के बीच हुई हिंसा की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय की अध्यक्षता में आयोग गठित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हिंसा के कुछ मामलों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से करायी जाएगी। गृहमंत्री ने अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ अभियान चलाने की भी घोषणा की और अवैध हथियार रखने वालों को पुलिस के सामने हथियार डालने को कहा। उन्होंने राज्य के लोगों को हिंसा की जांच निष्पक्ष रूप से कराने का आश्वासन दिया। शाह ने मणिपुर की यात्रा के चौथे और आखिरी दिन यहां यह घोषणा करते हुए कहा कि हिंसा में मारे गए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए पांच लाख रुपये राज्य और पांच लाख रुपये केन्द्र सरकार की ओर से दिए जाएंगे। यह राशि उनके निकट परिजनों के खाते में सीधे हस्तांतरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिंसा में घायल हुए लोगों और संपत्ति का नुकसान उठाने वालों के लिए एक राहत पैकेज की घोषणा कल गृह मंत्रालय द्वारा की जाएगी।

गृहमंत्री ने कहा कि मणिपुर के राज्यपाल की अध्यक्षता में शांति समिति बनाई जाएगी। गृहमंत्री ने मणिपुर के लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील किया। उन्होंने हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने का संकेत देते हुए कहा कि अवैध रूप से हथियार रखने वालों को पुलिस के सामने हथियार डालने होंगे। हथियारों की तलाशी के लिए कल से विशेष तलाशी अभियान शुरू किया जाएगा और जिनके प